Drishti IAS

करेंट अफेयर्स झारखंड

जून

2023

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

झारखंड **3**

➢ झारखंड कैबिनेट में 39 प्रस्तावों पर लगी मुहर 3

➢ झारखंड ने की स्पॉट टेस्टिंग शुरू 4

➢ मुख्यमंत्री ने एमएसएमई नीति के प्रस्ताव को दी मंजूरी 5

➢ झारखंड की प्रीति लकड़ा ने SGFI राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता काँस्य 6

➢ लोहरदगा के नदिया स्कूल के नाम में फिर से जोड़ा गया ‘हिन्दू’ शब्द 6

➢ झारखंड में खुलेगा यूनिटी मॉल 8

➢ चंद्रपुरा में 800 मेगावाट का लगेगा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट 8

➢ कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने ‘गोधन न्याय योजना’ का किया शुभारंभ 9

➢ विश्व परमाणु वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे झारखंड के गिरिडीह के कुणाल वर्मा 10

➢ ताइवान की हुआयु संवर्धन छात्रवृत्ति के लिये सीयूजे के पाँच विद्यार्थी हुए चयनित 11

➢ राज्यपाल ने ‘पारंपरिक योग’नाम से योग पुस्तक का किया विमोचन 12

➢ विक्की कुमार बने दुनिया के सबसे तेज पुरुष लेखक 13

➢ हजारीबाग में सीपीएस सिद्धू- कान्हू विद्यापीठ और छात्रावास की रखी गई आधारशिला 14

➢ चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल 15

➢ झारखंड कैबिनेट : निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने के लिये बनेगा डेडिकेटेड कमीशन, 43 प्रस्तावों पर लगी मुहर 16

➢ झारखंड को मिली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात 17

➢ राँची में पहली बार सी-20 चौपाल का आयोजन 18

➢ निरंजन कुजूर की विज्ञापन फिल्म ‘दि स्पिटिंग वॉल’को मिला ABBY'S Award 19

दृष्टि The Vision

नोट :

झारखंड

झारखंड कैबिनेट में 39 प्रस्तावों पर लगी मुहर

चर्चा में क्यों?

31 मई, 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें राज्य के पंचायत जनप्रतिनिधियों के विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी की स्वीकृति देने के साथ कुल 39 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

प्रमुख बिंदु

- कैबिनेट की बैठक में पंचायत जनप्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाए जाने पर स्वीकृति देने के बाद अब ज़िला परिषद् अध्यक्ष को 2 हज़ार रुपए, प्रमुख को आठ हज़ार और मुखिया को ढ़ाई हज़ार रुपए हर महीने मिलेंगे। इनके दैनिक भत्तों को भी बढ़ाकर हर पद के लिये 150 रुपए से 250 रुपए कर दी गई है।
- एसटी, एससी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा अन्य वर्ग की महिला प्रतिनिधियों, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन्हें विशिष मानदेय 100 की जगह 150 रुपए मिलेंगे। यात्रा भत्ता में भी संशोधन किया गया है। सभी को अब पाँच रुपए प्रति किमी. की जगह 10 रुपए प्रति किमी. की दर से यात्रा भत्ता मिलेगा।
- मंत्रिपरिषद् ने राज्य में जंगली जानवरों द्वारा जान-माल, फसल, पालतू जानवर एवं मकान को क्षति पहुँचाए जाने पर मिलने वाली मुआवजा की राशि में वृद्धि की है। इस तरह की घटनाओं में मनुष्य की मृत्यु होने पर पहले की तरह चार लाख रुपए ही मिलेंगे।
- वहीं मनुष्य के गंभीर रूप से घायल होने पर एक लाख की जगह 4.50 लाख, हल्का घायल होने पर 15 हज़ार की जगह 25 हज़ार रुपए, स्थायी रूप से अपंग होने पर दो लाख रुपए की जगह 3.25 लाख रुपए दिये जाएंगे। मकान को क्षति होने पर पहले एक लाख रुपए मिलते थे, इसे बढ़ाकर 1.20 लाख रुपए कर दिया गया है।
- कैबिनेट के अन्य महत्त्वपूर्ण फैसले:
    - झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक नियुक्ति नियमावली 2016 में संशोधन।
    - झारखंड राजस्व सेवा संवर्ग नियमावली 2023 का गठन।
    - गिरिडीह ज़िला के बगोदर सरिया अनुमंडल न्यायालय गठन की स्वीकृति।
    - वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये महालेखाकार का राज्य वित्त लेखा प्रतिवेदन उपस्थापन का अनुमोदन।
    - सी.वी. रमण ग्लोबल वि.वि. की स्थापना का अनुमोदन।
    - राज्य के स्कूली एवं राजकीय और अराजकीय पुस्तकालय की स्थापना विकास एवं विस्तारीकरण को मंज़ूरी।
    - झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग नियमावली-2013 में संशोधन।

झारखण्ड मंत्रालय
Chief Minister
Jharkhand

झारखंड ने की स्पॉट टेस्टिंग शुरू

चर्चा में क्यों ?

2 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड सरकार ने स्पॉट टेस्टिंग शुरू कर दी है, जिसके तहत ब्लॉक रिसोर्स पर्सन (बीआरपी)/क्लस्टर रिसोर्स पर्सन (सीआरपी) द्वारा स्कूल निरीक्षण के दौरान प्रत्येक स्कूल से तीन बच्चों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है।

प्रमुख बिंदु

- स्पॉट टेस्टिंग के तहत फिर सभी बच्चों का सर्वे किया जाता है कि जो चीजें बच्चों को सिखाई जा रही हैं, वे उन्हें कितना सीख पा रहे हैं। इस सर्वे में सभी छात्रों का हिन्दी, गणित और अंग्रेजी विषयों का परीक्षण किया जाता है, जहाँ बच्चों की बुनियादी साक्षरता और संख्या की जाँच की जाती है।
- स्पॉट टेस्टिंग के माध्यम से, महामारी से पहले के महीनों में झारखंड में प्रति माह 2 लाख बच्चों के सीखने के परिणाम डेटा एकत्र किये गए हैं। यह राज्य के सभी बच्चों का लगभग 5% है।
- बीआरपी और सीआरपी को मूल्यांकन पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया था और उच्च स्तर की सटीकता सुनिश्चित करने के लिये तार्किक जाँच और फील्ड सत्यापन की एक श्रृंखला के साथ डेटा को सत्यापित और क्रॉस-चेक किया गया था। समय के साथ डेटा में परिवर्तन 0.5-1% की सीमा तक सटीक होते हैं।
- नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पैमाने, ग्रैन्युलैरिटी, सटीकता और आवृत्ति को देखते हुए यह कहना सुरक्षित है कि झारखंड के पास दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे व्यापक शिक्षण डेटा सिस्टम है।
- राज्य ने एक लर्निंग ट्रैकिंग फॉर्मेट (एलटीएफ) भी स्थापित किया है, जहाँ प्रत्येक शिक्षक राज्य में प्रत्येक छात्र के लिये योग्यता स्तर का डेटा इनपुट करता है। स्पॉट टेस्टिंग के डेटा का उपयोग एलटीएफ डेटा को क्रॉस-सत्यापित करने और सटीकता सुनिश्चित करने के लिये किया जाएगा।
- इस सर्वेक्षण डेटा का उपयोग विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने के लिये किया जा रहा है :
  - ज़िला और ब्लॉक-वार मासिक प्रदर्शन विश्लेषण।
  - विशिष्ट पहलों का प्रभाव मूल्यांकन।
  - विशिष्ट कार्य योजनाओं को निर्धारित करने के लिये ज़िला और ब्लॉक समीक्षा में सीखने के डेटा का उपयोग।
  - शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिये विशिष्ट योग्यता अंतराल की पहचान।
  - पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तनों की पहचान जवाबदेही और इनाम प्रणाली।

मुख्यमंत्री ने एमएसएमई नीति के प्रस्ताव को दी मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

5 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड सरकार द्वारा तैयार की गई एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग) नीति के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंज़ूरी दे दी है। अब वित्त व विधि विभाग की मंज़ूरी के लिये इस प्रस्ताव को भेज दिया गया है, इसके बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार झारखंड सरकार ने एमएसएमई के लिये न केवल नीति बनाई है, बल्कि इसके लिये अलग निदेशालय का भी गठन करने जा रही है। निदेशालय के गठन के प्रस्ताव को प्रशासनिक पदवर्ग समिति की मंज़ूरी के लिये भेजा जाएगा।
- सरकार एमएसएमई उद्योगों को 10 करोड़ रुपए तक सब्सिडी देगी। साथ ही एमएसएमई उद्योगों द्वारा अपने कर्मचारियों के इपीएफ और इएसआई की राशि जमा करने पर सरकार प्रति कर्मचारी एक हज़ार रुपए प्रति माह की राशि भी देगी।
- झारखंड सरकार ने एमएसएमई नीति के प्रस्ताव में लिखा है कि झारखंड में पूर्व से 2.33 लाख एमएसएमई कार्यरत हैं। एमएसएमई सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा रोज़गार मिलता है और इसको ध्यान में रखते हुए एमएसएमई के लिये अलग से नीति बनाई गई है जिसका नाम एमएसएमई पॉलिसी 2023 रखा गया है।
- सरकार ने इसके उद्देश्यों के संबंध में कहा है कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य है एमएसएमई उद्योगों का विकास हो, ताकि रोज़गार का दरवाज़ा खुल सके। नीति में नये एमएसएमई उद्योगों के विकास के साथ-साथ पुराने उद्योगों के भी जीर्णोद्धार की बात कही गई है।
- प्रस्ताव में लिखा गया है कि एमएसएमई के लिये अलग से निदेशालय का गठन किया जाएगा और सभी ज़िलों में डिस्ट्रिक्ट एमएसएमई (डीएमसी) सेंटर भी खोला जाएगा।
- एमएसएमई निदेशालय पहली बार उद्योग लगा रहे उद्यमियों को पूरी सहायता करेगा। निदेशालय डीएमसी को मार्गदर्शन देगा और मॉनिटरिंग भी करेगा। साथ ही राज्य व केंद्र सरकार के एमएसएमई योजना और कार्यक्रमों को राज्य में लागू करेगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने का काम करेगा।
- एमएसएमई निदेशालय के आवश्यक निगम, बोर्ड या प्राधिकार का गठन करेगा, सब्सिडी व अन्य सहायता प्रदान करेगा। दूसरी ओर डीएमसी उद्यमियों को केंद्र व राज्य की योजनाओं का लाभ लेने में सहायता करेगा, उनके निबंधन से लेकर सिंगल विंडो क्लीयरेंस में सहायता करेगा, उद्यमियों को उद्योग लगाने में आ रही तकनीकी समस्याओं को दूर करेगा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उत्पादन व सेवा इकाइयों के विस्तार में सहयोग करेगा, नियमित रूप से कार्यशाला व प्रशिक्षण का आयोजन करेगा, एमएसएमई कलस्टर स्थापित करने में सहयोग करेगा।
- एमएसएमई को तीन वर्गों में बाँटा गया है- एक करोड़ रुपए तक की लागत वाले प्लांट माइक्रो इंटरप्राइज कहलाएंगे, 10 करोड़ तक की लागत वाले प्लांट स्मॉल इंटरप्राइज कहलाएंगे, वहीं 50 करोड़ रुपए की लागत और अधिकतम 250 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले प्लांट मीडियम इंटरप्राइज कहलाएंगे।
- झारखंड एमएसएमई पॉलिसी 2023 में कंप्रेहेंसिव प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इसके तहत माइक्रो इंटरप्राइजेज को एक करोड़ रुपए तक, स्मॉल इंटरप्राइजेज को पाँच करोड़ रुपए तक व मीडियम इंटरप्राइजेज को 10 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी।
- एसटी, एससी, महिला व दिव्यांग उद्यमी को पाँच प्रतिशत की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी, साथ ही स्टांप ड्यूटी व निबंधन में भी शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी।
- क्वालिटी सर्टिफिकेशन में भी सरकार 10 लाख रुपए तक की सहायता देगी, पेटेंट कराने पर भी 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
- विदेशों में उत्पाद ले जाने पर भी छूट : विदेशों में अपने उत्पादों की बिक्री के लिये किसी प्रदर्शनी में भाग लेने पर सरकार एक प्रदर्शनी के लिये चार लाख रुपए व एयर फेयर में 50 हज़ार रुपए की सहायता देगी।

झारखंड की प्रीति लकड़ा ने SGFI राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता काँस्य

चर्चा में क्यों ?

7 जून, 2023 को झारखंड की प्रीति लकड़ा ने भोपाल में आयोजित स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SGFI) राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में काँस्य पदक जीता।

प्रमुख बिंदु

- प्रीति लकड़ा ने ट्रिपल जंप इवेंट में 11.59 मीटर छलांग लगाकर यह पदक जीता है।
- विदित है कि प्रीति झारखंड सरकार के आवासीय प्रशिक्षण केंद्र (हज़ारीबाग) की प्रशिक्षु एथलीट है। इसी वर्ष उसने जूनियर फेडरेशन कप में भी रजत पदक जीता था।
- गौरतलब है कि खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। यह इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन और एशियन स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन की सक्रिय सदस्य भी है।
- यह संस्था भारत के स्कूलों में खेल के विकास तथा प्रचार-प्रसार की दिशा में कार्य करती है। इसमें देशभर के स्कूलों से अलग-अलग खेलों में रुचि रखने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन करके उनको उचित मंच दिया जाता है।

लोहरदगा के नदिया स्कूल के नाम में फिर से जोड़ा गया ‘हिन्दू’ शब्द

चर्चा में क्यों ?

7 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य के लोहरदगा ज़िले के नदिया हिन्दू हाई स्कूल में फिर से ‘हिन्दू’ शब्द जोड़ दिया गया है। पूर्व में जारी पत्र में विद्यालय के नाम से हिन्दू शब्द हटा दिया गया था।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने उत्कृष्ट विद्यालयों के पूर्व नाम में किये गए बदलाव को वापस ले लिया है। इस संबंध में 25 मई को जारी पत्र में संशोधन किया गया है। विभाग द्वारा इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है।
- राज्य के सात स्कूलों के नाम में फिर संशोधन किया गया है। अब स्कूलों के पूर्व के नाम में केवल सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जोड़ा जाएगा।
- चास बोकारो के रामरुद्र प्लस टू हाईस्कूल से हटाए गए 'रामरुद्र' शब्द को भी फिर स्कूल के नाम के साथ जोड़ दिया गया है।
- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा पूर्व में नाम में हुए बदलाव को टंकन में हुई गड़बड़ी बताया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में जारी पत्र की विसंगति में सुधार कर दिया गया है।
- पहले जारी लिस्ट में कुछ विद्यालयों के नाम दूसरे विद्यालय के साथ जोड़ दिये गए थे। बोकारो ज़िला के नवाडीह के विद्यालय के नाम में चास बोकारो जोड़ दिया गया था। ये गलतियाँ सुधार ली गई हैं।
- अब यह होंगे स्कूलों के नाम-
    - सीडी गर्ल्स सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस झुमरीतिलैया, कोडरमा।
    - एसएसएलएनटी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स, धनबाद।
    - डिस्ट्रिक्ट आरके रामा साहु सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, गढ़वा।
    - चंद्रवटी मेमोरियल सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, डोमचांच कोडरमा।
    - डिस्ट्रिक्ट रामरुद्र सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, चास बोकारो।
    - सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बीपीएम, बर्मामाइंस जमशेदपुर।
    - डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नदिया हिन्दू, लोहरदगा।

NADIA HINDU HIGH SCHOOL
1931
LOHARDAGA
+2 LEVEL

झारखंड में खुलेगा यूनिटी मॉल

चर्चा में क्यों ?

8 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड की राजधानी राँची में यूनिटी मॉल खुलेगा, जहाँ एक ही छत के नीचे लोग देवघर का पेड़ा, खरसावाँ के चिरौंजी के अलावा बिहार का जर्दालु आम, मखाना, लीची व ओडिशा का रसगुल्ला खरीद सकेंगे।

प्रमुख बिंदु

- इस मॉल में झारखंड के 24 ज़िलों के खास पहचान वाले उत्पादों के स्टॉल भी होंगे। वहीं, देश के सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के भी जीआई टैगवाले उत्पादों के स्टॉल होंगे। इसके लिये राज्य सरकार से राँची में चार से पाँच एकड़ ज़मीन की मांग की गई है।
- यूनिटी मॉल में एक ज़िला एक उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिये जगह मिलेगी। यही नहीं, इसमें दूसरे राज्यों के उत्पाद की बिक्री भी की जा सकेगी।
- गौरतलब है कि केंद्र सरकार के वाणिज्यकर मंत्रालय ने सभी राज्यों में यूनिटी मॉल खोलने के लिये ड्राफ्ट मांगे थे। झारखंड के उद्योग विभाग द्वारा राँची में यूनिटी मॉल खोलने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है।
- यूनिटी मॉल का निर्माण केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से होगा। इसके लिये केंद्र 50 करोड़ रुपए देगा।
- उल्लेखनीय है कि एक ज़िला एक उत्पाद योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य सभी राज्यों के हर ज़िला के एक उत्पाद को राष्ट्रीय पहचान देना है और स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध कराना है।
- इस योजना के अंतर्गत आनेवाले उद्योगों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी में रखा गया है। सरकार द्वारा इन उद्योगों को लगाने पर 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है।
- झारखंड में एक ज़िला एक उत्पाद चिह्नित-
    - ज़िला उत्पाद - देवघर व दुमका का पेड़ा, पू. सिहंभूम का टमाटर, हजारीबाग का गुड़, जामताड़ा की मिर्च, खूंटी का इमली, कोडरमा का नींबू, लोहरदगा का मधु, पाकुड़ का आम, रांची का अमरूद, साहिबगंज का आम, सरायकेला का चिरौंजी, प.सिंहभूम का शरीफा, बोकारो का कटहल, चतरा का टमाटर, धनबाद व गढ़वा का आलु, गिरिडीह का टमाटर, गोडन्न का आम, गुमला का हरी मिर्च, पलामू का टमाटर, रामगढ़ का पपीता, सिमडेगा का आम आदि।

चंद्रपुरा में 800 मेगावाट का लगेगा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट

चर्चा में क्यों ?

11 जून, 2023 को दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी) के चेयरमैन राम नरेश सिंह ने झारखंड के चंद्रपुरा स्थित निदेशक भवन में बताया कि चंद्रपुरा थर्मल की पुरानी यूनिटों का डिस्मैंटलिंग किया जा रहा है तथा एक नया सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट लगाने की योजना की जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- डीवीसी के चेयरमैन राम नरेश सिंह ने बताया कि राज्य में नया सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट लगाने हेतु सर्वे चल रहा है। ज़मीन की उपलब्धता तथा एश डाइक के लिये जगह मिलने पर यह प्लांट लगाया जाएगा।
- डीवीसी में सोलर के अलावा बैटरी स्टोरेज तथा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट भी लाया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। अगर चंद्रपुरा में किसी कारणवश सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट नहीं लग पाया तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लगाने की योजना है। इसके लिये यहाँ पर्याप्त पानी, मार्केट और स्टील प्लांट उपलब्ध है।
- डीवीसी के चेयरमैन ने कहा कि डीवीसी के बोकारो थर्मल में भी पुरानी यूनिट का डिस्मैंटलिंग जल्द शुरू होगा। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से रि-परपसिंग ऑफ ओल्ड यूनिट्स के बदले सोलर, रिन्युअल, बैटरी स्टोरेज या ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लगाने की दिशा में काम चल रहा है। इसके लिये सर्वे का काम चल रहा है।

- हाल में ही वर्ल्ड बैंक की टीम ने यहाँ का दौरा भी किया है। इसकी डीपीआर बन गई है और विद्युत मंत्रालय ने इस पर सहमति दे दी है।
- चेयरमैन ने कहा कि डीवीसी की विद्युत उत्पादन क्षमता सात हजार मेगावाट है। थर्मल पावर प्लांटों से उत्पादन क्षमता 6540 मेगावाट है। वर्तमान में डीवीसी के 250 मेगावाट तथा 210 मेगावट के दो थर्मल पावर प्लांट तकनीकी कारणों के कारण अंडर मेंटेनेंस हैं। डीवीसी ने पीक जेनरेशन कुल 5600 मेगावाट किया।
- वर्ष 2030 में डीवीसी की विद्युत उत्पादन क्षमता 14-15 हज़ार मेगावाट हो जाएगी। इसमें थर्मल, सोलर व ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट एवं बैटरी स्टोरेज प्लांट शामिल हैं। आने वाले समय में कोई ग्रीन फिल्ड पावर प्लांट नहीं लगाया जाएगा, बल्कि जहाँ डीवीसी के पुराने पावर प्लांट हैं, वहां नयी यूनिट स्थापित की जाएंगी।
- राज्य के रघुनाथपुर में 660 गुणा दो यानी 1320 मेगावाट क्षमता का प्लांट लगाया जाएगा। कोडरमा फेस दो में दो गुणा 800 यानी 1600 मेगावाट क्षमता का सुपर क्रिटिकल प्लांट लगाया जाएगा।
- इनके अलावा दुर्गापुर ओल्ड प्लांट की जगह 800 मेगावाट क्षमता का नया पावर प्लांट लगाया जाएगा। यहाँ के पुराने प्लांट का ऑक्शन प्रोसेस में है। यानि आने वाले सात साल में 3720 मेगावाट क्षमता के नए पावर प्लांट लगाये जाएंगे। करीब दो हजार क्षमता का सोलर प्लांट लगाया जाएगा।
- डीवीसी के कुल चार डैम हैं, जिससे फ्लोटिंग क्षमता 18-19 सौ मेगावाट जेनरेशन की है। कई पावर प्लांट के अंदर वाटर रिजरवॉयर भी हैं। आने वाले समय में कोडरमा में 10 मेगावाट, चार पावर प्लांट के वाटर रिजरवॉयर से 30 मेगावाट, तिलैया व पंचेत डैम से 310 मेगावाट के अलावा एक अन्य आठ मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगेगा।
- इसके अलावा पंप स्टोरेज का भी बड़ा प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। मैथन में एक हज़ार तथा ललपनिया में 15 सौ मेगावाट क्षमता का पंप स्टोरेज प्लांट लगाया जाएगा।
- चेयरमैन ने कहा कि ललपनिया के लुगू पहाड़ में 15 सौ मेगावाट क्षमता का पंप स्टोरेज प्लांट प्रस्तावित है। शुरु में कुछ ग्रामीण यहाँ प्लांट लगाने का विरोध कर रहे थे। लेकिन अब ग्रामीणों का सकारात्मक सहयोग मिल रहा है।

कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने 'गोधन न्याय योजना' का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

12 जून, 2023 को झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने हेसाग स्थित पशुपालन विभाग के सभागार में 'गोधन न्याय योजना'का शुभारंभ किया। योजना के प्रथम चरण में करीब 10 हजार किसान लाभान्वित होंगे।

प्रमुख बिंदु

- कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य के पाँच ज़िलों से गोधन न्याय योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की जा रही है। इस प्रोजेक्ट की सफलता की समीक्षा के बाद पूरे राज्य में इसे चलाने की योजना बनाई जाएगी।
- इस योजना का उद्देश्य झारखंड में उपलब्ध गोवंश के द्वारा उत्सर्जित गोबर का उपयोग वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हुए कृषक की रासायनिक खादों पर निर्भरता को कम करने एवं कृषकों की आय में वृद्धि करना है।
- विदित है कि गोवंश द्वारा उत्सर्जित गोबर कृषि के पारिस्थितिकी तंत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये मिटी के जलधारण क्षमता को बढ़ाते हुए मिट्टी की जैविक मात्रा में वृद्धि करते हैं। गोबर को कृषि कार्यों में प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिये एक प्रभावी प्रबंधन की ज़रूरत है, जो कृषकों के लिये लाभदायक होगा।
- पूरे राज्य में उत्पादित गोबर को गोपालकों से क्रय कर वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित कर अनुदानित दर पर कृषकों को उपलब्ध कराने का ये पायलट प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट की शुरुआत वर्तमान समय में प्रत्येक प्रमंडल के एक ज़िला से की जा रही है।
- कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद्य पदार्थों का उपयोग हो, राज्य के उत्पादों को जैविक की मान्यता मिले, इसके लिये एजेंसी और सेंटर बनाने की तैयारी सरकार कर रही है।
- वर्मी कंपोस्ट के लिए 10 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।अगर यह सफल रहा, तो 100 करोड़ की योजना भी बनाई है जाएगी। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को 8 रुपए किलो वर्मी कंपोस्ट उनके इलाके में ही उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही गोपालकों से 2 रुपए किलो गोबर सरकार लेगी और प्रसंस्करण के बाद किसानों को वर्मी कंपोस्ट के रूप में उपलब्ध कराएगी।

The Vision

- महालिंगा शिवाजी ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड के सीईओ महालिंगा शिवाजी ने कहा कि इस योजना से 504 लाख मीट्रिक टन उत्सर्जित गोबर की नाइट्रोजन के रूप में कन्वर्ट किया जा सकेगा और इस कन्वर्जन से राज्य को 22000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है।
- साल 2019 के आर्थिक सर्वे के अनुसार राज्य में 12.57 मिलियन गोवंश हैं। एक अनुमान के तौर पर गोवंश के द्वारा 504 लाख टन गोबर का उत्सर्जन प्रति वर्ष किया जाता है।
- गोधन न्याय योजना का लक्ष्य: पशुपालकों की आय में वृद्धि, पशुधन विचरण एवं खुली चराई पर रोक, जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा एवं रसायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना, स्थानीय स्तर पर जैविक खाद की उपलब्धता, स्थानीय स्वयं सहायता समूह/ बेरोज़गार युवकों को रोजगार के अवसर/गोशालाओं का सुदृढ़ीकरण, भूमि की उर्वरता को बढ़ाने में मदद एवं रासायनरहित खाद पदार्थों की उपलब्धता।

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड
ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखण्ड (ओफाज)
झारखण्ड जैविक कृषि प्राधिकार
- 2023

विश्व परमाणु वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे झारखंड के गिरिडीह के कुणाल वर्मा

चर्चा में क्यों ?

18 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के गिरिडीह ज़िले के कुणाल वर्मा यूरोप के वियना में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित विश्व परमाणु वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 19 जून से 27 जून तक परमाणु वैज्ञानिकों की एक कॉन्फ्रेंस यूरोप के वियना में आयोजित की जा रही है। कॉन्फ्रेंस में यूएनओ के सदस्य देशों के परमाणु वैज्ञानिक भाग लेंगे।
- भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले कुणाल वर्मा ने आईआईटी हरिद्वार से बीटेक किया और फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से एमटेक इन न्यूक्लीयर साइंस में पढ़ाई पूरी की।
- वर्तमान में वह भारत सरकार के न्यूक्लीयर फ्यूल्स कॉम्प्लेक्स में परमाणु वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत् हैं।

ताइवान की हुआयु संवर्धन छात्रवृत्ति के लिये सीयूजे के पाँच विद्यार्थी हुए चयनित

चर्चा में क्यों?

19 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार ताइवान के शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2023-2024 के शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिये 'हुआयु संवर्धन छात्रवृत्ति'का रिजल्ट जारी किया, जिसमें राँची के झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के सुदूर पूर्व भाषा विभाग के पाँच चीनी भाषा सीखने वाले छात्रों को इस छात्रवृत्ति के लिये चुना गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस छात्रवृत्ति के तहत झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के इन सभी छात्रों को ताइवान जाने और रहने के दौरान अपनी भाषा कौशल को बढ़ाने में सक्षम बनाया जाएगा।
- छात्रा प्राची गोयल और छात्र राहुल कुमार को ताइवान जाने और वहाँ पर रहकर भाषा संवर्धन के लिये 6 महीने की स्कॉलरशिप दी गई है।
- विदित है कि हाल ही में प्राची गोयल और राहुल कुमार ने 22वीं चीनी ब्रिज प्रतियोगिता में अपने चीनी भाषा कौशल का शानदार प्रदर्शन किया था।
- सौरभ कुमार, रिंशु कुमार सिंह और आशुतोष कुमार को ताइवान में रहकर चीनी भाषा कौशल को विकसित करने के लिये 3 महीने की छात्रवृत्ति दी गई है। ये छात्र वहाँ की मूल संस्कृति और भाषा का गहराई से अध्ययन करेंगे।
- ज्ञातव्य है कि चीनी भाषा चित्रात्मक लिपि होने के कारण विश्व की सबसे कठिन भाषा मानी जाती है।
- वर्तमान समय में झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय पूर्वी भारत में चीनी भाषा सीखने के एक बड़े केंद्र के रूप में उभरा है, जहाँ से चीनी भाषा की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भारत के अन्य विश्वविद्यालयों की अपेक्षा सबसे अधिक छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है।
- चीनी भाषा सीखने के लिये प्रत्येक वर्ष इस विश्वविद्यालय में भारत के अनेक हिस्सों से विद्यार्थी यहाँ आते हैं। चीनी भाषा सीखने का क्रेज इस कदर है कि इस साल 31 सीटों के लिये 3500 से ज़्यादा आवेदकों ने अप्लाई किया।
- विश्वविद्यालय के इस विभाग में बेहतरीन शिक्षकों के साथ-साथ बेहतर चीनी भाषा प्रयोगशाला एवं श्रव्य-दृश्य प्रयोगशाला की सुविधा है, जो चीनी भाषा सीखने वालों को काफी मदद करती है।

- चीनी भाषा विशेषज्ञ और सीयूजे के शिक्षक सुशांत कुमार ने बताया कि आज चीनी भाषा की बाज़ार में काफी मांग है। रोज़गार की दृष्टि से भी अन्य भाषाओं के मुकाबले इसमें रोज़गार अधिक है। इसलिये इस भाषा की दिनोंदिन मांग बढ़ती जा रही है।

राज्यपाल ने 'पारंपरिक योग' नाम से योग पुस्तक का किया विमोचन

चर्चा में क्यों ?

20 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 'पारंपरिक योग' नाम से योग पुस्तक का राजभवन में विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- योग पुस्तक 'पारंपरिक योग' डॉ. परिणीता सिंह और डॉ. अर्चना कुमारी ने लिखी है।
- डॉ. परिणीता सिंह ने बताया कि योग पर आधारित यह उनकी तीसरी पुस्तक है। इससे पहले उन्होंने 'योग एक दृष्टि में' और 'अभ्यास' नाम की पुस्तकें भी लिखी हैं।
- उन्होंने कहा कि वे इस पुस्तक के माध्यम से भारतीय संस्कृति के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त करना चाहते हैं। यह पुस्तक सभी आयु वर्ग के लिये उपयोगी है।
- वहीं डॉ. अर्चना कुमारी ने कहा कि 'पारंपरिक योग' में योग के सूक्ष्म ज्ञान को सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दोनों रूप में बताने का प्रयास किया गया है। इस पुस्तक में सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है।
- डॉ. परिणीता सिंह राँची विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ योगा में गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्यरत हैं, जबकि डॉ. अर्चना कुमारी राज्य योग केंद्र, आयुष निदेशालय और झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग में योग प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत हैं।

विक्की कुमार बने दुनिया के सबसे तेज पुरुष लेखक

चर्चा में क्यों ?

19 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के बोकारो ज़िले के अंतर्गत फुसरो के सुभाषनगर निवासी 21 वर्षीय लिविंग आइकॉन पॉल उर्फ विक्की कुमार चार दिनों में किताब लिखकर दुनिया के सबसे तेज पुरुष लेखक बने हैं।

प्रमुख बिंदु

- वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से उन्हें उनकी किताब 'द टॉपर ऑफ नेवर वेंट टू कॉलेज' के लिये यह वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है। विक्की का यह तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
- विदित है कि उनकी पहली किताब 'द टॉपर ऑफ नेवर वेंट टू स्कूल' थी।
- विक्की ने यह किताब अपने पिता भरत राम और मां भवानी देवी को समर्पित किया है।
- विक्की कुमार का कहना है कि यह किताब हर उस स्टूडेंट के लिये है, जो स्कूल और कॉलेज में फेल हो गए थे या अच्छा नहीं कर पाये।
- इस किताब में बताया गया कि कैसे कोई स्टूडेंट कुछ नियम और कुछ एक्टिविटी कर सक्सेसफुल लाइफ टॉपर बन सकता है।
- विक्की लाइफ टॉपर कोच, लेखक और पब्लिक स्पीकर भी हैं। उन्होंने जोश टॉक्स में भी अपनी कहानी सुनाई है।

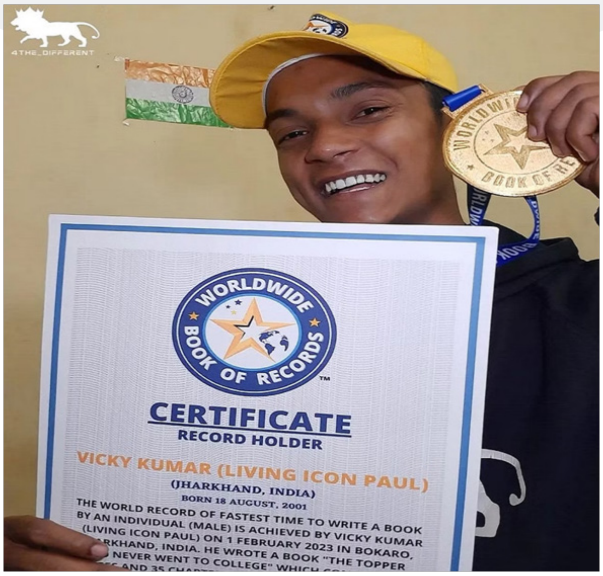
4THE_DIFFERENT
WORLDWIDE BOOK OF RECORDS
CERTIFICATE
RECORD HOLDER
VICKY KUMAR (LIVING ICON PAUL)
(JHARKHAND, INDIA)
BORN 18 AUGUST, 2001
THE WORLD RECORD OF FASTEST TIME TO WRITE A BOOK
BY AN INDIVIDUAL (MALE) IS ACHIEVED BY VICKY KUMAR
(LIVING ICON PAUL) ON 1 FEBRUARY 2023 IN BOKARO,
RKHAND, INDIA. HE WROTE A BOOK "THE TOPPER
NEVER WENT TO COLLEGE" WHICH

नोट :

हजारीबाग में सीपीएस सिद्धू- कान्हूं विद्यापीठ और छात्रावास की रखी गई आधारशिला

चर्चा में क्यों ?

21 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के हजारीबाग के सदर प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब बच्चों को सीबीएसई बोर्ड आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये स्कूल छात्रावास उपलब्ध कराने हेतु हजारीबाग के सिद्धू-कान्हू सेवा संस्थान एवं कोलकाता की संस्था पिंजरापोल सोसाइटी द्वारा सीतागढ़ा गौशाला में सीपीएस सिद्धू- कान्हूं विद्यापीठ एवं छात्रावास का भूमि पूजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- हजारीबाग के सीतागढ़ा गौशाला परिसर में 2000 बच्चों का सीबीएसई बोर्ड आधारित यह स्कूल होगा, जहाँ 1000 बच्चों का आवासीय व्यवस्था उपलब्ध रहेगा।
- आवासीय परिसर में भारतीय संस्कृति और सभ्यता भारतीय प्राचीन गुरुकुल की संपूर्ण झलक दिखेगी।
- 22 एकड़ भूखंड में प्रकृति की खूबसूरत वादियों के बीच यह विद्यालय अपने आप में अनोखा और उत्कृष्ट होगा।

CPS सिद्धो कान्हू विद्यापीठ एवं छात्रावास
शिलान्यास सामारोह
दिनांक : 21 जून 2023
स्थान : सीतागढ़ा गौशाला, चू रोड, हरीबाग

चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल

चर्चा में क्यों ?

23 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार राँची के सरला बिरला विश्वविद्यालय में चित्रपट झारखंड द्वारा तीन दिवसीय फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया, जिसमें कुल 60 फिल्मों को प्रदर्शित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- तीन दिवसीय फिल्म फेस्टिवल में फिल्म के निर्माता-निर्देशकों को प्रमाण पत्र से नवाज़ा गया।
- इस फिल्म महोत्सव में चित्रपट झारखंड द्वारा प्रतियोगिता के लिये फिल्मों के 10 विषय रखे गए थे। इनमें जनजातीय समाज, झारखंड स्वतंत्रता संग्राम, वोकल फॉर लोकल, झारखंड का इतिहास, ग्राम विकास, महिला सशक्तीकरण, पर्यावरण, सामाजिक सद्भाव, रोज़गार सृजन, भविष्य का भारत जैसे विषय थे।
- इस फिल्म फेस्टिवल में फिल्मों की पुरस्कार श्रेणी तीन प्रकार की रखी गई थी - लघु फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कैंपस फिल्म।
- इन तीनों कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ तीन पुरस्कार दिये गए। तीनों प्रकार की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार दिया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता एवं सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री के साथ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को भी पुरस्कृत किया गया।
- लघु फिल्म पुरस्कार की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म प्रथम को 31000 रुपए, द्वितीय को 21 हज़ार रुपए एवं सर्वश्रेष्ठ तृतीय फिल्म को 11000 रुपए प्रदान किये गए।
- सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को 5100 रुपए, सर्वश्रेष्ठ कहानी को 5100 रुपए, सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफर को 5100 रुपए एवं सर्वश्रेष्ठ संपादक को भी 5100 रुपए से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता को 5100 रुपए एवं सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री को 5100 रुपए प्रदान किये गए।
- फिल्म पुरस्कार की डॉक्यूमेंट्री फिल्म की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को 31000 रुपए, द्वितीय सर्वश्रेष्ठ फिल्म को 21000 रुपए एवं तृतीय सर्वश्रेष्ठ फिल्म को 11000 रुपए से नवाज़ा गया। कैंपस फिल्म की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म 15000 रुपए, द्वितीय 11000 रुपए एवं तृतीय श्रेणी में 7500 रुपए प्रदान किये गए।
- सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को 3100 रुपए, सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता को 3100 रुपए व सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री को 31 हजार रुपए से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के साथ एक ट्रॉफी और प्रमाण पत्र भी दिया गया।
- समापन समारोह पर पूर्व मंत्री एवं विधायक सरयू राय ने विजयी प्रतिभागियों को सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया।

चित्रपट झारखण्ड
समारोह

नोट :

झारखंड कैबिनेट : निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने के लिये बनेगा डेडिकेटेड कमीशन, 43 प्रस्तावों पर लगी मुहर

चर्चा में क्यों?

26 जून, 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 43 प्रस्तावों पर सहमति दी गई। इसके तहत निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने के लिये डेडिकेटेड कमीशन बनेगा। पिछड़ा वर्ग आयोग ही डेडिकेटेड कमीशन के रूप में काम करेगा।

प्रमुख बिंदु

- झारखंड कैबिनेट ने राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण की पात्रता की जाँच के लिये 'डेडिकेटेड कमीशन' बनाने का फैसला किया है। पिछड़ा वर्ग आयोग ही डेडिकेटेड कमीशन के रूप में काम करेगा। 'विकास कृष्णा राव गवली बनाम महाराष्ट्र सरकार' के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए फैसले के मद्देनज़र कमीशन के गठन का फैसला किया गया है।
- कैबिनेट ने राज्य की आंगनबाड़ी सेविकाओं और महिला पर्यवेक्षिकाओं को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की। केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी व पोषण 20.0 के तहत पोषण अभियान योजना में कुल 29,100 सेविकाओं और पर्यवेक्षिकाओं को अधिकतम आठ हज़ार रुपए (जीएसटी अतिरिक्त) का स्मार्ट फोन दिया जायेगा। इसके अलावा कुल 6,850 आंगनबाड़ी केंद्रों का भी उन्नयन किया जाएगा। इसके लिये प्रति आंगनबाड़ी केंद्र एक लाख रुपए खर्च किये जाएंगे।
- कैबिनेट ने राज्य में महिलाओं से नाइट शिफ्ट में भी काम लेने के प्रस्ताव पर सहमति दी। इसके लिये 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के तहत भारत सरकार द्वारा तैयार किये गए बिजनेस रिफॉर्मस एक्शन प्लान के अनुपालन कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन का फैसला किया तथा कारखाना संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान की।
    - इसके पहले राज्य के औद्योगिक संस्थानों में महिलाओं से सुबह 10 बजे से शाम पाँच बजे तक ही काम लेने की अनुमति थी। अधिनियम में संशोधन के फैसले से महिलाओं से शाम पाँच बजे से सुबह 10 बजे तक यानी नाइट शिफ्ट में भी काम लिया जा सकेगा।
- कैबिनेट ने झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक, 2023 के गठन को स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत अब शपथपत्र व वकालतनामा आदि में इस्तेमाल किये जाने वाले स्टांप शुल्क की दर में वृद्धि कर दी गई है।
    - पूर्व में शपथपत्र व वकालतनामा में 15 रुपए का स्टांप लगाना होता था। अब 30 रुपए के स्टांप का इस्तेमाल किया जाएगा। स्टांप से विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि अधिवक्ताओं के कल्याण पर खर्च की जाएगी।
- कैबिनेट ने गोड्डा के महागामा में 500 बेड वाले अस्पताल के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव पर मंजूरी दी। अस्पताल का निर्माण इसीएल सीएसआर से करेगा। कुल 307.44 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। कैबिनेट ने इसे पीपीपी मोड पर चलाने की स्वीकृति प्रदान की।
- कैबिनेट द्वारा 'नमामि गंगे योजना' के तहत धनबाद में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पर सहमति दी गई। इस पर 858.86 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे। योजना का संचालन पीपीपी मोड पर किया जाएगा।

झारखण्ड मंत्रालय

झारखंड को मिली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात

चर्चा में क्यों ?

27 जून, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से राँची-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर ऑनलाइन उद्घाटन किया, जिसके साथ ही वंदे भारत राँची से पटना के लिये रवाना हो गई।

प्रमुख बिंदु

- राँची-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस झारखंड और बिहार के लिये पहली वंदे भारत रेलगाड़ी है।
- राँची-पटना नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पटना से प्रस्थान करेगी और गया, कोडरमा, हजारीबाग, बरकाकाना तथा मेसरा रेलवे स्टेशनों पर रुकते हुए उसी दिन राँची स्टेशन पहुँचेगी।
- प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधनों से समृद्ध राँची खनिज आधारित उद्योगों के लिये एक आदर्श स्थान है। यह ट्रेन स्थानीय व्यापारियों और कारोबारियों के लिये पटना के साथ तेज कनेक्टिविटी स्थापित करने की दृष्टि से लाभदायक साबित होगी।
- पटना और राँची के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने वाली यह रेलगाड़ी पर्यटकों, छात्रों और व्यवसायियों के लिये वरदान साबित होगी।
- वंदे भारत एक्सप्रेस के रवाना होने के पहले दिन विभिन्न स्कूलों के बच्चों को फ्री में सफर कराया गया।
- विदित है कि अब देश में कुल 23 वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। ये ट्रेनें विभिन्न मार्गों पर वर्तमान में सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों की तुलना में यात्रा के समय में कई घंटों की बचत कर रही हैं।
- वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों को विश्वस्तरीय अनुभव प्रदान करेगी और पर्यटन को बढ़ावा देगी।

शुभारंभ
वंदे भारत एक्सप्रेस का पीएम मोदी
ने किया ऑनलाइन उद्घाटन

राँची में पहली बार सी-20 चौपाल का आयोजन

चर्चा में क्यों ?

27 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार सिटीजंस फाउंडेशन और सेवा इंटरनेशनल की ओर से झारखंड की राजधानी राँची में पहली बार सी-20 चौपाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सेवा, सेवा की भावना, परोपकार और स्वयं सेवकवाद विषय के कई पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

प्रमुख बिंदु

- इस कार्यक्रम में झारखंड में कार्यरत विभिन्न समाजिक संगठनों के संचालक तथा समाजसेवी, सिविल सोसाइटी संगठन के प्रतिनिधि, कॉरपोरेट कंपनियों के सीएसआर प्रमुख तथा शैक्षणिक संस्थानों के महत्त्वपूर्ण स्कॉलरों ने भाग लिया।
- तीन सत्रों में आयोजित इस कार्यक्रम के पहले सत्र का संचालन मुक्ति मिशन की फाउंडर रश्मि साहा ने किया, जिसमें बतौर पैनलिस्ट सिनी झारखंड की स्टेट प्रोग्राम मैनेजर तनवी झा, पालोना संस्था की फाउंडर मोनिका आर्या, एएफसी इंडिया लिमिटेड की राज्य परियोजना निदेशक रिचा चौधरी ने 'सेवा की भावना'विषय पर विस्तार से चर्चा की और सामान्य जीवन पर इसके प्रभाव तथा सामाजिक महत्त्व के बारे में बताया।
- इसी तरह दूसरे सत्र में लाइव सेवर्स, राँची के फाउंडर और समाजसेवी अतुल गेरा, राइज अप के फाउंडर ऋषभ आनंद तथा केजीवीके संस्था के संचिव डॉ. अरविंद सहाय ने बतौर पैनलिस्ट संयुक्त रूप से भाग लिया और 'सामाजिक विकास के क्षेत्र में स्वयंसेवा की भावना' विषय पर विचार रखे।
- सामजिक स्तर पर स्वयंसेवा क्यों महत्त्पूर्ण है और इसके क्या-क्या सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। इस सत्र का संचालन राजीव गुप्ता ने किया।
- सी-20 चौपाल कार्यक्रम के अंतिम और विशेष सत्र संचालक संगीत नाटक अकादमी (भारत) के सदस्य एवं लोक और जनजातीय कला के सलाहकार नंदलाल नायक ने किया, जिसमें पैनलिस्ट के रूप में उषा मार्टिन के सीएसआर हेड डॉ. मयंक मुरारी, पारस अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉ. संजय कुमार तथा आइलिड एचआर की फाउंडर तथा एचआर कंसल्टेंट कनिका मल्होत्रा ने 'सामुदायिक परोपकार'विषय पर विस्तार से चर्चा की।
- कार्यक्रम के समापन सत्र के दौरान सिटीजन फाउंडेशन के सीइओ गणेश रेड्डी ने कहा कि ऐसे सामाजिक हितों के कार्यक्रमों से राज्यहित से जुड़ी कई योजनाओं के सफल संचालन में मदद मिलती है।

G20
sewa International
C20 CHAUPAL

निरंजन कुजूर की विज्ञापन फिल्म 'दि स्पिटिंग वॉल' को मिला ABBY'S Award

चर्चा में क्यों ?

28 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के युवा फिल्मकार निरंजन कुजूर के विज्ञापन फिल्म 'दि स्पिटिंग वॉल' को विज्ञापन जगत का प्रतिष्ठित पुरस्कार एबिज अवॉर्ड (ABBY'S Award) गोवा फेस्ट के दौरान दिया गया।

प्रमुख बिंदु

- यह अवॉर्ड एडवरटाइजिंग क्लब के 54वें संस्करण में दिया गया। विज्ञापन जगत में इसे साउथ एशिया का का सबसे बड़ा अवॉर्ड माना जाता है।
- निरंजन कुजूर की यह एड फिल्म 'नो टोबैको डे' के दिन रिलीज हुई। यह एक डिजिटल एड फिल्म है जिसे सोशल मीडिया में साल 2022 में रिलीज किया गया था।
- निरंजन कुमार ने बताया कि 'दि स्पिटिंग वॉल' विज्ञापन को डाबर रेड पेस्ट के सहयोग से बनाया गया है।
- एड फिल्म को स्पेशलिस्ट कैटेगरी में कॉउज मार्केटिंग के लिये पुरस्कार दिया गया। एड फिल्म की शूटिंग कोलकाता और नोएडा में हुई है।
- एड फिल्म का उद्देश्य पान-गुटखा खाने वाले को जागरूक करना है। एक कृत्रिम वॉल को जरिया बनाकर बहुत ही खूबसूरती के साथ इस विज्ञापन में आम लोगों को तंबाकू सेवन से बचने की सलाह दी गई है।
- निरंजन वर्ष 2020 से एड फिल्म बना रहा है। अब तक उसने पाँच एड फिल्म बनाई है, जिसमें से दो को अवार्ड मिला है।
- 'दि स्पिटिंग वॉल' को अब तक दो पुरस्कार मिल चुके हैं। एड गली का मोबेक्स अवॉर्ड भी इस फिल्म को मिला है। इसके अलावा 'डाबर रत्नप्राश' को इकोनोमिक्स टाइम्स का बेस्ट यूज्ड ऑफ कंटेंट मार्किटिंग का अवार्ड भी मिला है।
- विदित है कि राज्य के युवा फिल्मकार निरंजन कुजूर की कुडुख भाषा में बनी फिल्म 'एड़पा काना' को नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में बेस्ट ऑडियोग्राफी के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।
- उल्लेखनीय है कि निरंजन कुजूर झारखंड के लोहरदगा ज़िले के रहने वाले निदेशक और पटकथा लेखक हैं। अब तक निरंजन ने कुड़ुख, हिन्दी, बांग्ला और संताली भाषा में फिल्म बनाई है।

The Vision

- हाल ही में निरंजन ने बांग्ला में शार्ट फिल्म 'तीरे बेंधो ना'बनाई है, जिसे केरल के IDSFFK aur SiGNS फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाएगा। उसके बाद इसे कोलकाता में South Asian Short Film Festival (SASFF) में भी दिखाया जाएगा।

The Vision